भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या- *20
सोमवार, 22 जुलाई, 2024/31 आषाढ़, 1946 (शक)

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट

***20. श्री रामप्रीत मंडल:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की इस रिपोर्ट से सहमत है कि भारत में युवाओं की बेरोजगारी दर अब वैश्विक स्तर से अधिक है;
(ख) क्या यह सच है कि भारतीय अर्थव्यवस्था शिक्षित युवाओं के लिए पर्याप्त नौकरियों का सृजन नहीं कर पाई है;
(ग) क्या तथाकथित जिग नौकरियों में वृद्धि अथवा अस्थायी और कम वेतन वाले रोजगार भारत में रोजगार की स्थिति के लिए चिंताजनक हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मुद्दों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार मंत्री
(डॉ मनसुख मंडाविया)

एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**

"अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट" के संबंध में श्री रामप्रीत मंडल द्वारा पूछे गए लोक सभा के दिनांक 22-07-2024 के तारांकित प्रश्न संख्या *20 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): मानव विकास संस्थान (आईएचडी) - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की भारत रोजगार रिपोर्ट, 2024 में उल्लेख किया गया है कि आईएलओ की ग्लोबल रिपोर्ट ट्रेंड्स फॉर यूथ, 2022 में, दुनिया भर में वर्ष 2021 में युवा बेरोजगारी दर 15.6 प्रतिशत थी। इसके अलावा, आईएलओ द्वारा विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान, 2024 के अनुसार, वैश्विक स्तर पर, 2023 में युवा बेरोजगारी दर 13.3 प्रतिशत थी।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) वर्तमान में भारत में रोजगार/बेरोजगारी संकेतक के अधिकारिक डाटा स्रोत है। इस सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति के आधार पर 15-29 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवाओं की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) निम्नानुसार हैः

वर्ष	बेरोजगारी दर (%)
2017-18	17.8
2018-19	17.3
2019-20	15.0
2020-21	12.9
2021-22	12.4
2022-23	10.0

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

उपरोक्त आंकड़ें दर्शाते हैं कि देश में युवाओं की बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृत्ति है। इसके साथ-साथ, भारत में युवाओं की बेरोजगारी दर दुनिया भर में युवा बेरोजगारी दर से कम रही है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रकाशित केएलईएमएस (के: पूंजी, एल: श्रम, ई: ऊर्जा, एम: सामग्री और एस: सेवाएं) डेटाबेस अखिल भारतीय स्तर पर रोजगार के रुझान प्रदान करता है। डेटाबेस के नवीनतम आंकड़ों, 2023-24 के अनंतिम अनुमान के अनुसार, देश में रोजगार 2017-18 में 47.5 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 में बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया। 2017-18 से 2023-24 के दौरान रोजगार में कुल वृद्धि लगभग 16.83 करोड़ है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का पेरोल डेटा औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के स्तर को दर्शाता है। वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 1.3 करोड़ से अधिक अभिदाता ईपीएफओ में शामिल हुए। इसके साथ-साथ, पिछले साढ़े छह वर्षों के दौरान (सितंबर 2017 से मार्च 2024 तक) कुल 6.2 करोड़ से अधिक अभिदाता ईपीएफओ में शामिल हुए हैं, जो रोजगार के औपचारिकीकरण में वृद्धि का संकेत देता है।

सभी श्रम बल संकेतक देश में सकारात्मक रोजगार परिदृश्य का प्रमाण दे रहे हैं।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश भर में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय आदि विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं जैसे प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्व-रोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों के विवरण को https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

*****